भारत के सर्वोच्च न्यायालय

याचिकाकर्ता:

केदार नाथ सिंह

बनाम

प्रतिवादीः

बिहार राज्य

निर्णय की तारीखः

20/01/1962

पीठः

सिन्हा, भुवनेश्वर पी. (मुख्य न्यायाधीश)

पीठः

सिन्हा, भुवनेश्वर पी. (मुख्य न्यायाधीश)

दास एस. के.

सरकार, ए. के.

अयानगर, एन. राजगोपाला

मुधोलकर, जे. आर.

उद्धरणः

1962 ए. आई. आर. 955 1962 एस. सी. आर. सप्ल.(2) 769

उद्धरणकर्ता:

आर	1963 एससी 996 (5)
आर	1964 एससी1230 (9)
आर.एफ.	1967 एस. सी. 1877 (22)
डी	1970 एससी 2015 (12)
आरएफ	1973 एससी1091 (6)
डी	1980 एससी 354 (5)
आर.एफ.	1980 एस. सी. 1042 (11)
ई	1991 एससी 101 (28,69,227,278)

अधिनियम:

राजद्रोह-कानून की सामग्री राजद्रोह और सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान की संवैधानिकता-क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है-भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम XLV), धाराएँ,124 ए, 505-भारत का संविधान, अनुच्छेद (19)(1)(ए), 19 (2)।

हेडनोटः

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है, संवैधानिक रूप से वैध है। यद्यपि यह धारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हैं और मौलिक अधिकार के साथ अनुमेय

विधायी हस्तक्षेप के दायरे में हैं। धारा 124 ए के दायरे के सवाल पर एक संघर्ष संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बीच है। संघीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शब्द, कार्य या लेखन धारा 124 ए के तहत एक अपराध संस्थापित करता है। केवल तभी जब उनका इरादा या प्रवृत्ति सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने, सार्वजनिक अशांति पैदा करने या अव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हो, जबकि प्रिवी काउंसिल ने यह विचार लिया है कि यह धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध का एक आवश्यक घटक नहीं था। कि शब्द आदि, सार्वजनिक अव्यवस्था को उत्तेजित करने का इरादा या संभावना का हो। कोई भी दृष्टिकोण लिया जा सकता है एवं अच्छे कारणों से समर्थित किया जा सकता है। यदि संघीय न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया गया था,धारा 124 ए का उपयोग संवैधानिक होगा लेकिन यदि प्रिवी काउंसिल के विचार को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह असंवैधानिक होगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि एक तरह से माने गए कानून के कुछ प्रावधान उन्हें संविधान के अनुरूप बना देंगे, और एक अन्य व्याख्या उन्हें असंवैधानिक बना देगी, तो न्यायालय पूर्व निर्माण के पक्ष में झुक जाएगा। धारा 124 ए की शुरुआत के कारणों और राजद्रोह के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस धारा का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसका उपयोग अव्यवस्था पैदा करने के इरादे या प्रवृत्ति, या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी या हिंसा के लिए उकसाने वाले कार्यों तक सीमित हो।

इसके बाद निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम राजा सम्राट, (1942) एफ. सी. आर. 38 आया।

राजा एम्परर बनाम सदाशिव नारायण भालेराव, (1947) एल. आर. 74 आई. ए. 89 और वालेस जॉनसन बनाम द किंग (1940) ए. सी. 331 का अनुसरण नहीं किया गया।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। (1050) एससीआर 594। बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य। (1950) एस. सी. आर. 605 और रामजी लाल मोदी बनाम यू. पी. राज्य (1957) एस. सी. आर. 860, संदर्भित।

बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1955) 2 एस. सी. आर. 603 और आर. एम. डी. चमारबौगवाला बनाम भारत संघ, [1957] एस. सी. आर. 930 अनुपयुक्त हुआ।

सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान देने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के अपराध के प्रत्येक घटक तत्व, भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत दंडनीय हैं, का राज्य या सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए संदर्भ और उस पर सीधा प्रभाव था। अतः धारा 505 का प्रावधान अनुच्छेद 19 (2) द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था।

निर्णय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार - 1957 की आपराधिक अपील सं. 169।

1955 की अपराधिक अपील सं. 445 में पटना उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल, 1956 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

1958 की आपराधिक अपील सं. 124 से 126 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 16 मई, 1958 के निर्णय और आदेश से आपराधिक अपील संख्या 76 और 1955 की 108 और 1955 की अपराधिक एम. रिट सं.- 2371 में अपील।

1957 की आपराधिक अपील सं. 169 में अपीलार्थी के लिए जनार्दन शर्माः-अपीलार्थी को धाराएँ 124 ए एवं 505 के तहत दोषी ठहराया गया है। .ये दोनों धाराएँ अधिकार से बाहर हैं क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। एक भाषण सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, लेकिन दोनों

को धारा 124 ए के तहत दंडनीय बनाया गया है। यह धारा दोनों प्रकार के स्वीकार्य भाषणों और अस्वीकार्य भाषणों के भाषणों को प्रभावित करता है। धारा 124 ए का स्पष्टीकरण मुख्य धारा की व्याख्या को प्रभावित नहीं करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ताकि उसे बदला जा सके। मामलों में दो प्रश्न उठते हैं, अर्थात् (i) क्या धारा 124 ए 124 एक ऐसी विधि अधिनियमित करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो और (ii) क्या यह धारा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाती है। आई. एल. आर. (1958) 2 सभी 84 में निर्णय जिसने धारा 124 ए को अधिकार से परे होना घोषित किया है, सही कानून लेता है। 124 ए को अधिकार से परे होना सही कानून लेता है।

1957 की आपराधिक अपील संख्या 169 में प्रत्यर्थी के लिए आर. सी. प्रसादः-रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1957] एस.सी.आर. 860 में निर्णय का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि वह श्री सी. बी. अग्रवाल द्वारा की जाने वाली दलीलों को स्वीकार करेंगे।

1958 की आपराधिक अपील संख्या 124 से 126 में अपीलार्थी के लिए सी. बी. अग्रवाल: वर्तमान व्यवस्था और संविधान के मामले में धारा 124 ए के प्रावधानों का सही अर्थ का वह है जो संघीय न्यायालय द्वारा निहारेन्दु दत्त के मामले, 1942 एफ. सी. आर. 38 में दिया गया है, न कि भालेराव के मामले 74 आई. ए. 89 में प्रिवी काउंसिल द्वारा उन्हें दिया गया अर्थ। समाज के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में बदलाव और इसके उचित सदस्यों की राय के साथ तथ्यों के एक विशेष समूह के लिए कानूनों के शब्दों की अदालतों द्वारा व्याख्या बदल रही है। धारा 124 ए एक अध्याय में है जो राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। इसलिए, यह किसी भी अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि राज्य के खिलाफ अपराध है। राजद्रोह से संबंधित अंग्रेजी कानून में शब्द

इंग्लैंड के कानून पर स्टीफन की टिप्पणी, खंड 4, पृष्ठ 141, हैल्सबरीज़ लॉ ऑफ़ इंग्लैंड का तीसरा संस्करण, खंड। 10, पृष्ठ 169 जोविट का अंग्रेजी कानून का शब्दकोश, पृष्ठ 1605, स्टीफन का आपराधिक कानून का इतिहास, खंड। 2, पृष्ठ 298 और 301 अध्याय 24 धारा 124 ए के समान है। अंग्रेजी कानून के तहत हंगामा या अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति राजद्रोह का एक अनिवार्य तत्व है। अपराधों पर रसेल, खंड 1,पी. 229, आर. वी.कोलिन्स, 173 ई. आर. 910.आर. वी.सुलिवन, 11 कॉक्स। 44.धारा 124 ए को अंग्रेजी कानून से लिया गया है (22 बॉम देखें। 152)। इसलिए, धारा 124 ए की व्याख्या उसी तरीके से की जानी चाहिए जैसे इंग्लैंड में राजद्रोह की व्याख्या की जाती है और यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की प्रवृत्ति धारा 124 ए के तहत अपराध का एक अनिवार्य तत्व है। कनाडाई आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 133 और 133 ए, जो राजद्रोह से संबंधित हैं, 1951, कनाडाई एस. सी. आर. 265 के समान व्याख्या दी गई है। तिलक के मामले 22 बॉम 1112, भालेराव के मामले में 74 आई. ए. 89 और वालिस जॉनसन के मामले में [1940] ए. सी. 331 में लिया गया दृष्टिकोण कि हिंसा के लिए उकसाना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की प्रवृत्ति धारा 124 ए का एक आवश्यक घटक नहीं था। सही दृष्टिकोण नहीं है। 1942 एफ. सी. आर. 38 सही दृष्टिकोण रखता है और यह निर्धारित करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की प्रवृत्ति धारा 124 ए के तहत अपराध का एक आवश्यक घटक है। देवी सरन का मामला 32 पैट 1124 भी यही दृष्टिकोण रखता है।

न्यायालय के समक्ष धारा 124 ए की दो व्याख्याएँ है, एक संघीय न्यायालय द्वारा लिया गया और दूसरा प्रिवी काउंसिल द्वारा लिया गया। इस न्यायालय को धारा न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह व्याख्या धारा को संवैधानिक बना देगी। भले ही प्रिवी काउंसिल द्वारा दी गई व्याख्या को सही माना जाए, फिर भी धारा 124 ए वैध रहेगी। इस धारा में निश्चित रूप से ऐसे मामलों पर विचार किया गया है जहां

भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने की संभावना है एवं जैसा कि अनुच्छेद 19 (2) में विचार की गई सार्वजनिक व्यवस्था के हित में धारा और केवल यह तथ्य कि कुछ मामले जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने की संभावना नहीं है, भी इसमें शामिल हैं, धारा को अमान्य नहीं कर सकते हैं। इस अदालत ने रामजीलाल मोदी के मामले [1957] एस. सी. आर. 860 में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया और विरेंद्र के मामले [1958] एस. सी. आर. 308 में, निर्णय लोहिया का मामला [1960] 2 एस. सी. आर. 821 इस मामले को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उस मामले में यह पाया गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने वाले प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं थे क्योंकि प्रावधानों और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के बीच का संबंध बहुत दूर था। भले ही धारा को प्रिवी काउंसिल के दृष्टिकोण के अनुसार माना जाए, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है और जिन्हें धारा के संबंध में वैध ठहराया जा सकता है, जहां सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है क्योंकि दोनों मामले अलग-अलग हैं। [1957] एस. सी. आर. 930, [1941] एफ. सी. 72 [1951] एस. सी. आर. 682, [1953] 1059 और 65 एल. एड, 1139।

संघीय न्यायालय के संविधान विकृति के अनुच्छेद 374 (2) के महान्यायवादी के लिए पी. वर्मा को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के रूप में सही माना जाएगा। 1942 एफ. सी. आर. 38 में संघीय न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय का निर्णय माना जाना चाहिए और इसे बाध्यकारी माना जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की प्रवृत्ति धारा 124 ए में स्वयं में निहित है।

1958 की आपराधिक अपील संख्या 124 में प्रतिवादी के लिए गोपाल बिहारीः प्रिवी काउंसिल द्वारा धारा 124 ए की व्याख्या को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अंग्रेजी कानून में भी राजद्रोह में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का इरादा शामिल नहीं है, 79 सी. एल. आर. 101। स्पष्टीकरण (2) और (3) निरर्थक होंगे यदि धारा 124 ए की

व्याख्या राजद्रोह के अंग्रेजी दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों ने धारा 124 ए की समान व्याख्या दी है,जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने किया है। देखें 1941 ऑल 156, 1930 लाह 309, 56 कैल 1085 और 10 लक 712. लोहिया के मामले में भी निर्णय [1960] 2 एस. सी. आर. 821 वर्तमान मामले को नियंत्रित करता है और धारा 124 ए ऐसे भाषणों को भी दंडित करती है जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोई प्रवृत्ति नहीं है और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद 19 (2) द्वारा सहेजा नहीं गया है क्योंकि ऐसे भाषणों पर प्रतिबंध लगाना सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं है। न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह अपने दायरे से ऐसे भाषणों को हटाकर धारा को फिर से लिखे, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है और इसे ऐसे भाषणों तक सीमित रखे, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की प्रवृत्ति हो। पूरा खंड विफल होना चाहिए; इसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता है।

सी. बी. अग्रवाल ने जवाब दियाः-अंग्रेजी कानून में राजद्रोही इरादे का एक आवश्यक घटक है जिसमें हंगामा या डी. आर. वी. पैदा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अलरेड, 22 कॉक्स। सी. सी. 1, आर. वी.बर्डॉट, 101,803; आर. वी. ओ 'ब्रायन, 6 सेंट ट्र. (एनएस)571. परिषद ने केवल यह कहा है कि वास्तविक हिंसा को उकसाना इसका एक आवश्यक घटक नहीं था। यह आगे नहीं बढ़ा है और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की प्रवृत्ति नहीं है जो धारा 124 ए की सामग्री नही थी। भले ही जनता अपराध का एक घटक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक भाषणों या लेखन को बाधित करने की प्रवृत्ति है जो कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजना या असंतोष को लाती है या उत्तेजित करने के लिए लायी जाती है।

1962. 20 जनवरी न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधीश सिन्हा द्वारा घोषित किया गया- इन अपीलों में विवाद का मुख्य सवाल यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 124 ए और 505 संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के प्रावधानों को देखते हुए अमान्य हो गई हैं। धारा 124 ए के प्रावधानों की संवैधानिकता जिसका मुख्य रूप से हमारे सामने प्रचार किया गया था, सभी अपीलों के लिए सामान्य है, जिसके तथ्यों को जल्द ही अलग से कहा जा सकता है।

1957 की आपराधिक अपील 169 में, अपीलकर्ता एक केदार नाथ सिंह है, जिस पर बिहार के मुंगेर जिले के बेगुसराय में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ निम्नलिखित आरोप बनाए, जो उसके खिलाफ आरोप की गंभीरता को सामने लाने के लिए विस्तार से निर्धारित किए गए हैं।

> "सबसे पहले- कि आप 26 मई, 1953 को बरौनी ग्राम, पी. एस. तघरा (मुंगेर) में शब्द बोलते हुए, (ए) आज सी. आई. डी. के कुत्ते बरौनी के चारों ओर घूम रहे हैं। इस बैठक में भी कई आधिकारिक कुत्ते बैठे हैं। भारत के लोगों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया और इन कांग्रेस के गुंडों को गद्दी के लिए चुना और उन्हें उस पर बैठा दिया। आज ये कांग्रेस के गुंडे लोगों की गलती के कारण गद्दी पर बैठे हैं। जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो हम इन कांग्रेस के गुंडों पर भी हमला करेंगे और उन्हें बाहर निकाल देंगे। इन कांग्रेस के गुंडों के साथ इन आधिकारिक कुत्तों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस के गुंडे अमेरिकी डॉलर पर भरोसा कर रहे हैं और आज लोगों पर विभिन्न प्रकार के कर लगा रहे हैं। हमारे भाइयों-मज़दूरों और किशनों का खून चूसा जा रहा है। इस देश के पूंजीपति और जमींदार इन कांग्रेस के गुंडों की मदद करते हैं। इन कांग्रेस के गुंडों के साथ इन जमींदारों और पूंजीपतियों को भी जनता के दरबार में लाना होगा।

(बी) किसानों और मजदूरों के संगठन और एकता के बल पर फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के गुंडों के काले कामों को उजागर करेगी, जो अंग्रेजों की तरह हैं। केवल शरीर का रंग बदल गया है। उन्होंने आज देश में लाठियों और गोलियों का नियम स्थापित किया है। अंग्रेजों को इस भूमि से दूर जाना पड़ा। उनके पास हवाई जहाज, बंदूकें, बम और अन्य हथियार थे।

(सी) फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं वोट के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। पार्टी हमेशा क्रांति में विश्वास करती रही है और वर्तमान में भी करती है। हम उस क्रांति में विश्वास करते हैं, जो आएगी और जिसकी लपटों में भारत के पूंजीपति, जमींदार और कांग्रेस के नेता, जिन्होंने देश को लूटना अपना पेशा बना लिया है, राख हो जाएंगे और उनकी राख पर भारत के गरीबों और दलित लोगों की सरकार स्थापित होगी।

(डी) कांग्रेसियों से कुछ भी उम्मीद करना एक गलती होगी। उन्होंने (कांग्रेस शासकों ने) लोगों का ध्यान उनकी गलतियों से हटाने के लिए लोगों के बीच में वी. भावे को लंगोट पहनाकर खड़ा किया है। आज विनोवा भारतीय राजनीति के मंच पर एक नाटक खेल रही हैं। लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। मैं विनोवा से कहना चाहता हूं और उसके एजेंटों को सलाह देना चाहता हूं, "आपको यह समझना चाहिए कि विनोवा के इस भ्रम और धोखाधड़ी से लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। "मैं कांग्रेसियों के बीच विनोवा को कठपुतली बनने नहीं दूंगी। ये लोग, विनोवा की योजना को समझते हैं, महसूस करते हैं कि विनोवा कांग्रेस सरकार के एजेंट है।

(ई) मैं आपको बताता हूं कि यह कांग्रेस सरकार आपका कोई भला नहीं करेगी।

(एफ) मैं कांग्रेस के तानाशाहों से भी आखिरी शब्द कहना चाहता हूं, "आप लोगों के साथ खेलते हैं और उन्हें रिश्वत, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा कर बर्बाद करते हैं। आज-कल गरीबों के बच्चे भोजन के लिए तरस रहे हैं और आप कांग्रेस के लोग कुर्सियों पर बैठे नवाबों का रवैया अपना रहे हैं।

भारतीय संघ में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने या उत्तेजित करने या असंतोष भड़काने का प्रयास किया और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।...."

दूसरा- कि आपने 26 मई, 1953 को बरौनी ग्राम में, थाना तेगरा (मुंगेर) ने बयान दिया, अर्थात, (क) आज सी. आई. डी. के कुत्ते बरौनी के चारों ओर घूम रहे हैं। इस बैठक में भी कई आधिकारिक कुत्ते बैठे हैं। भारत के लोगों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया, और इन कांग्रेस के गुंडों को गद्दी के लिए चुना और उन्हें उस पर बैठा दिया। आज ये कांग्रेस के गुंडे लोगों की गलती के कारण गद्दी पर बैठे हैं। जब हम अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे, तो हम इन कांग्रेस के गुंडों पर हमला करेंगे और उन्हें बाहर निकाल चुके है,ये कांग्रेस के गुंडे अमेरिकी डॉलर पर भरोसा कर रहे हैं और आज लोगों पर विभिन्न प्रकार के कर लगा रहे हैं। हमारे मजदूर भाईयों और किसानों का खून चूसा जा रहा है। इस देश के पूंजीपति और जमींदार इन कांग्रेस गुंडों की मदद करते हैं। इन कांग्रेस के गुंडों के साथ इन जमींदारों और पूंजीपतियों को भी जनता के दरबार में लाना होगा।

(बी) किसानों और मजदूरों के संगठन और एकता के बल पर फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के गुंडों के काले कामों को उजागर करेगी, जो अंग्रेजों की तरह हैं। केवल शरीर का रंग बदल गया है। उन्होंने आज देश में लाठियों और

गोलियों का नियम स्थापित किया है। अंग्रेजों को इस भूमि से दूर जाना पड़ा। उनके पास हवाई जहाज, बंदूकें, बम और अन्य कारण थे।

(सी) फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं मतों के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है। पार्टी हमेशा क्रांति में विश्वास करती रही है और वर्तमान में भी करती है। हम उस क्रांति में विश्वास करते हैं, जो आएगी और जिसकी लपटों में भारत के पूंजीपति, जमींदार और कांग्रेस के नेता, जिन्होंने देश को लूटना अपना पेशा बना लिया है, राख हो जाएंगे और उनकी राख पर भारत के गरीबों और दलित लोगों की सरकार स्थापित होगी।

(डी) कांग्रेस शासकों से कुछ भी उम्मीद करना एक गलती होगी। उन्होंने (कांग्रेस शासकों ने) लोगों का ध्यान उनकी गलतियों से हटाने के लिए लोगों के बीच में वी. भावे को लंगोट पहनाकर खड़ा किया है। विनोबा आज भारतीय राजनीति के मंच पर एक नाटक खेल रही हैं। लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है। मैं विनोवा से कहना चाहता हूं और उसके एजेंटों को सलाह देना चाहता हूं, "आपको यह समझना चाहिए कि विनोवा की इस योजना, भ्रम और धोखाधड़ी से लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। मैं विनोवा को सलाह दूंगा कि वे कांग्रेसियों के हाथों की कठपुतली न बनें। जो लोग विनोवा की योजना को समझते हैं, उन्हें एहसास होता है कि विनोवा कांग्रेस सरकार की प्रतिनिधि हैं।

(ई) मैं आपको बताता हूं कि इस कांग्रेस सरकार से आपका कोई भला नहीं होगा।

(एफ) मैं कांग्रेस के तानाशाहों से भी आखिरी शब्द कहना चाहता हूं "आप लोगों के साथ खेलते हैं और उन्हें रिश्वत, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के जाल में

फंसाकर बर्बाद करते हैं। आज गरीबों के बच्चे भोजन के लिए तरस रहे हैं और आप (कांग्रेस के लोग) कुर्सियों पर बैठे नवाबों का रवैया अपना रहे हैं।...."

जनता में भय या भय पैदा करने के इरादे से या जिससे किसी भी व्यक्ति को बिहार राज्य के खिलाफ और सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (बी) के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

मौखिक साक्ष्य की पर्याप्त मात्रा दर्ज करने के बाद, विद्वत विचारण मजिस्ट्रेट ने आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की दोनो धाराओं 124 ए एवं 505 (बी) के तहत उन्हें एक साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद की धारा के तहत दोषसिद्धि के संबंध में कोई अलग सजा पारित नहीं की गई थी।

दोषी व्यक्तियों ने पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसकी सुनवाई स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री नकी इमाम ने अकेले बैठकर की। 9 अप्रैल, 1956 के इस फैसले और आदेश द्वारा, उन्होंने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया। अपने निर्णय के दौरान, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप सरकार की निंदा के अलावा और कुछ नहीं है; कि यह क्रांति के लिए उकसावे से भरा था और समग्र रूप से लिया गया भाषण निश्चित रूप से राजद्रोह था। यह किसी भी उपाय की आलोचना करने वाला भाषण नहीं है। उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि अपराध भारतीय दंड संहिता की दोनो धाराओं 124 ए एवं 505 (बी) के तहत बनाई गई थी।

दोषी व्यक्ति ने इस अदालत का रुख किया और अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की। यह ध्यान दिया जाएगा कि उन धाराओं के प्रावधानों की संवैधानिकता जिसके तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि हुई थी, उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार नहीं किया गया

था। लेकिन विशेष अनुमति के लिए याचिका में, इस न्यायालय में, आधार लिया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए और 505 "संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ असंगत हैं। "इस अदालत में पहली बार 5 मई, 1959 को एक खंड पीठ द्वारा अपील की सुनवाई की गई थी। पीठ ने पाया कि विद्वान वकील ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए एवं 505 की वैधता के बारे में संवैधानिकता मुद्दा उठाया था, ने निर्देश दिया कि अपील को संविधान पीठ द्वारा सुनवाई के लिए रखा जाए। इसके बाद इस मामले को 4 नवंबर, 1960 को एक संविधान पीठ के समक्ष रखा गया, जब उस पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय नियमों के नियम 1, 0.41 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। .इस मामले को एक बार फिर 9 फरवरी, 1961 को एक संविधान पीठ के समक्ष रखा गया था, जब इसे दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि इस अपील से संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ 1958 की संबंधित आपराधिक अपील संख्या-124-126 (जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपीलकर्ता है) को भी गद्य-दस्तावेजों के संबंध में अपना मन बनाने में सक्षम बनाया जा सके, साथ ही इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कि विधि आयोग नई व्यवस्था को देखते हुए राजद्रोह के कानून में संशोधन के प्रश्न पर विचार कर रहा था। चूंकि संबंधित राज्यों ने अपने वकील को अपील करने का निर्देश दिया है, इसलिए मामला आखिरकार हमारे सामने आ गया है।

1958 के आपराधिक अपील संख्या- 124-126 में उत्तर प्रदेश राज्य अपीलार्थी है, हालांकि उत्तरदाता अलग हैं। 1958 की आपराधिक अपील 124 में, अभियुक्त व्यक्ति मोहम्मद, इशाक इहाही है। 30 अक्टूबर को अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अलीगढ़ में भाषण देने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। उस अवसर पर उनके भाषण को राजद्रोही माना गया था। आवश्यक मंजूरी के बाद, दंडाधिकारी ने एक जांच की, और आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया वाद बनने का पता लगाने के बाद, उसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 8 जनवरी, 1955 के

अपने निर्णय द्वारा उन्हें धारा 153 ए के तहत आरोप से बरी कर दिया, लेकिन उसे भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए के तहत अन्य आरोप के लिए दोषी ठहराया, एवं उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिकता को चुनौती दी। 1958 की आपराधिक अपील संख्या 125 में तथ्य यह है कि 29 मई, 1954 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हनुमानगंज ग्राम में बोल्शोविक पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। उस अवसर पर, प्रतिवादी राम नंद को एक आपत्तिजनक भाषण देते हुए पाया गया था क्योंकि उन्होंने कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा के उपयोग की वकालत की थी। अभियोजन पक्ष के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने एक जांच की और अंततः उसे सत्र न्यायालय के समक्ष अपना मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध किया। नियत समय में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत दोषी ठहराया एवं उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने माना कि आरोपी व्यक्ति ने हथियारों के उपयोग से कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ खुले तौर पर हिंसक विद्रोह के लिए दर्शकों को उकसाकर अपराध किया था। दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त आदेश के खिलाफ, अभियुक्त व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी।

1958 की आपराधिक अपील 126 में, प्रतिवादी एक पारसनाथ त्रिपाठी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 26 सितंबर, 1955 को फैजाबाद जिले के थाना अकबरपुर ग्राम के मानसपुर में एक भाषण दिया था, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने श्रोताओं को एक स्वयंसेवक सेना को संगठित करने और सरकार और उसके सेवकों का हिंसक तरीकों से विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ घृणा और शत्रुता की भावना पैदा करने के इरादे से दर्शकों को उत्साहित किया था। जब उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया,

अभियुक्त व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन इस आधार पर किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के प्रावधानों में उनकी नजरबंदी अवैध थी एवं संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रुप में अमान्य था। ...यह मामला, उन अपीलों के साथ, जिसके द्वारा अपील संख्या 124 और 125 को जन्म दिया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अंततः एक पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें देसाई, गुरतू और बेग न्यायाधीशगण शामिल थे। विद्वान न्यायाधीशों ने अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णयों में यह विचार रखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अधिकार से बाहर था। मामले के उस दृष्टिकोण में, उन्होंने दो अपील संख्या 124 और 125 में उपरोक्त रूप से दोषी ठहराए गए अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया और आपराधिक अपील संख्या 126 में अभियुक्त की रिट याचिका को मंजूरी दे दी। इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान किया कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। इस प्रकार ये अपीलें पूर्व के जरीये उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए योग्यता प्रमाण पत्र पर है। उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के समर्थन में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए श्री सी. बी. अग्रवाल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय (राम नंदन बनाम राज्य (1) में प्रतिवेदित किया गया है जिसमें यह पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) से परे था और, इसलिए, इस कारण से शून्य था कि यह सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं था और वहाँ लगाए गए प्रतिबंध भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं थे, गलत था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित धारा अनुच्छेद 19 के खंड (2) के भीतर आती है और इसके विपरीत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण गलत थे। उन्होंने निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम राजा एम्परर (1) में संघीय न्यायालय की टिप्पणियों पर

भरोसा किया। उन्होंने इंग्लैंड के कानूनों पर स्टीफन की टिप्पणियों, खंड IV, 21 वें संस्करण, पृष्ठ 141, और हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों में कानून के कथन, तीसरे संस्करण, खंड 10, पृष्ठ 569 और उन खंडों में संदर्भित मामलों पर भी भरोसा किया। इलाहाबाद मामलों में प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए श्री गोपाल बिहारी ने अपने पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर पूरी तरह से भरोसा किया है। पटना उच्च न्यायालय की अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश हुए श्री शर्मा ने इसी तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा किया है।

पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों से निपटने से पहले, कानून के इतिहास, उसके द्वारा किए गए संशोधनों और धारा 124 ए के प्रावधानो पर रखी गई व्याख्या भारत में न्यायालयों द्वारा, और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के उनके प्रभुत्व द्वारा निर्धारित करना सुविधाजनक है। धारा 124 ए के अनुरुप धारा मुल रुप से 1837-39 के मैकाले मसौदा दंड संहिता की धारा 113 था, लेकिन भारतीय दंड संहिता से धारा हटा दिया गया था क्योंकि यह 1860 में अधिनिमित था। अधिनिमित संहिता से छूट का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शायद विधायी निकाय ने संहिता में इस तरह के प्रावधान को लागू करने के लिए अपने प्राधिकार से ऊपर सुनिश्चित महसूस नहीं किया। जो भी हो,धारा 124 ए को 1870 के अधिनियम XXVII द्वारा 1870 तक संविधि पुस्तक में नहीं रखा गया था। सर जेम्स, स्टीफन द्वारा संशोधन पेश किए जाने के समय काफी चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने विधायिका में विधेयक पेश करते समय जो कहा वह हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है। उस समय अधिनियमित धारा इस प्रकार थीः

"124 ए. उत्साहजनक असंतोष -

जो कोई भी शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या पढ़ने के इरादे से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार

के प्रति असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित करता है, या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन या किसी भी अवधि के लिए परिवहन से दंडित किया जाएगा जिसमे जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास की एक अवधि के साथ, जिसे तीन वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण-सरकार के विधिसम्मत प्राधिकार का पालन करने और उस प्राधिकरण को नष्ट करने या उसका विरोध करने के गैरकानूनी प्रयासों के खिलाफ सरकार के विधिसम्मत प्राधिकरण का समर्थन करने के स्वभाव के अनुरूप सरकार के उपायों की अस्वीकृति, असंतोष नहीं है। इसलिए, केवल इस प्रकार की अस्वीकृति को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार के उपायों पर टिप्पणी करना इस खंड के भीतर अपराध नहीं है।

भारत में इस धारा के तहत उत्पन्न होने वाला पहला मामला वह है जिसे बंगोबासी मामले (क्वीन-एम्प्रेस बनाम जगेंद्र चंदर बोस (1)) के रूप में जाना जाता है, जिसकी सुनवाई सर कॉमर पेथेरम, सी. जे. के समक्ष एक जूरी द्वारा की गई थी, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने जूरी को इन शब्दों में कानून की व्याख्या कीः

"असंतोष का अर्थ है स्नेह के विपरीत भावना, दूसरे शब्दों में, नापसंद या घृणा। अस्वीकृति का अर्थ है केवल अस्वीकृति। पुरुषों की भावनाओं या कार्यों को अस्वीकार करना और फिर भी उन्हें पसंद करना काफी संभव है। इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना अलग है कि मुझे लगता है कि आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्री जैक्सन के विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों के मन में जिनको संबोधित किए गए है, ऐसी मनोवृत्ति पैदा करने के लिए बोले गए या लिखित शब्दों का उपयोग करता है जो सरकार के वैध अधिकार का

पालन नहीं करते हैं, या उस अधिकार को नष्ट करने या विरोध करने के लिए, यदि और जब अवसर उत्पन्न होना चाहिए, और यदि वह अपने धारकों या पाठकों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा करने के इरादे से ऐसा करता है, तो वह धारा के अर्थ के भीतर असंतोष पैदा करने का प्रयास करने के अपराध का दोषी होगा, हालांकि उनके शब्दों या वास्तव में उनके द्वारा उत्पन्न किसी भी असंतोष की भावना से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। यह धारा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है कि उपयोग किए गए शब्दों की गणना सरकार के खिलाफ दुर्भावना की भावनाओं को भड़काने और इसे लोगों की घृणा और अवमानना के लिए रखने के लिए की गई है, और उनका उपयोग ऐसी भावना पैदा करने के इरादे से किया गया था।

अगला मामला रानी-साम्राज्ञी बनाम बाल्कनकद्दर तिलक (1) का प्रसिद्ध मामला है जो बोबे उच्च न्यायालय के समक्ष आया था। इस मामले की सुनवाई एक जूरी द्वारा स्ट्रैची, जे. के समक्ष की गई थी। विद्वान न्यायाधीश, जूरी को अपने आरोप के दौरान, उन्हें इन शब्दों में कानून की व्याख्या करते हैंः

"पहले खंड द्वारा परिभाषित अपराध सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को उत्तेजक या उत्तेजित करने का प्रयास है। "असंतोष की भावनाएँ" क्या हैं?मैं बंगोबासी मामले में सर कॉमर पेथेरम से सहमत हूं कि असंतोष का मतलब केवल स्नेह का अभाव है। इसका अर्थ है घृणा, शत्रुता नापसंद, विद्वेष, अवमानना और सरकार के प्रति हर प्रकार की दुर्भावना। "बेवफाई" शायद सबसे अच्छा सामान्य शब्द है, जो सरकार के प्रति हर संभव बुरी भावना को समझता है। असंतोष से कानून का जो अर्थ है, वह यह है कि एक व्यक्ति को इसे उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास नही करना चाहिए, उसे दूसरो को सरकार के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता की अनुभूति नही करानी चाहिए या कराने की चेष्टा नही करनी चाहिए। आप देखेंगे कि

शायद सजा के सवाल से निपटने के अलावा असंतोष की मात्रा या तीव्रता बिल्कुल मायने नहीं रखती हैः यदि कोई व्यक्ति बड़े या छोटे असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, तो वह धारा के तहत दोषी है। दूसरी स्थिति में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्नगत प्रकाशन से असंतोष की कोई भावना उत्तेजित हुई है या नहीं। यह सच है कि आपके सामने प्रत्येक कैदी के खिलाफ एक आरोप है कि उसने वास्तव में सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित किया है। यदि आप संतुष्ट हैं कि उसने ऐसा किया है, तो आप निश्चित रूप से उसे दोषी पाएँगे। लेकिन अगर आपको यह मानना चाहिए कि यह आरोप नहीं बनाया गया है, और यह साबित होता है कि कोई भी इन लेखों को पढ़कर सरकार के प्रति असंतोष की भावनाओं को महसूस करने के लिए विचारित नहीं था, तो भी यह अकेले आपको कैदियों को बरी करने के लिए उचित नहीं होगा। उनमें से प्रत्येक के लिए न केवल असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया जाता है, बल्कि ऐसी भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास भी किया जाता है। आप देखेंगे कि यह खंड असंतोष की भावनाओं के सफल उत्तेजना और उन्हें उत्तेजित करने के असफल प्रयास को बिल्कुल एक ही आधार पर रखता है, ताकि, यदि आप पाते हैं कि कैदियों में से किसी ने दूसरों में ऐसी भावना को उत्तेजित करने की कोशिश की है, तो आपको उसे दोषी ठहराना होगा, भले ही यह दिखाने के लिए कुछ भी न हो कि वह सफल हुआ। एक बार फिर यह महत्वपूर्ण है कि आपको एक और बात का पूरी तरह से एहसास होना चाहिए। अपराध में सरकार के प्रति दूसरों की कुछ बुरी भावनाओं को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना शामिल है। यह विद्रोह या बगावत को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास नहीं है, या किसी भी प्रकार की बड़ी या छोटी वास्तविक अशांति नहीं है। वहाँ की वस्तुओं के कारण कोई गड़बड़ी या प्रकोप हुआ था या नहीं, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता है।

> यदि अभियुक्त का इरादा लेखों द्वारा विद्रोह या अशांति को भड़काने का था, तो उसका कार्य निस्संदेह धारा 124 ए के अंतर्गत आएगा, और संभवतः दंड संहिता की अन्य धाराओं के अंतर्गत आएगा। लेकिन भले ही उन्होंने सरकार के अधिकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह या प्रकोप या जबरन प्रतिरोध को न तो उकसाया और न ही उकसाने का इरादा किया हो, फिर भी अगर उन्होंने सरकार के प्रति शत्रुता की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, तो यह धारा के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। मुझे पता है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सोचा है कि धारा के खिलाफ कोई अपराध नहीं हो सकता है, जब तक कि अभियुक्त सरकार को या तो सलाह नहीं देता या विद्रोह या जबरन प्रतिरोध का सुझाव नहीं देता है। मेरी राय में, यह दृष्टिकोण स्वयं इस धारा के व्यक्त शब्दों के बिल्कुल विपरीत है, जो जहां तक संभव हो सके स्पष्ट रूप से अपराध की परीक्षा में कुछ भावनाओं को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, न कि विद्रोह या जबरन प्रतिरोध जैसे किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने का प्रयास है। मैं इस तरह के विचार के लिए केवल इस धारा से जुड़े स्पष्टीकरण को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ने और इसके वास्तविक दायरे से परे स्पष्टीकरण के गलत उपयोग को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं।

बाद में जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए लंबा उद्धरण आवश्यक हो गया है, अर्थात्, विद्वान न्यायाधीश द्वारा कानून का यह बयान बहुत अधिक टिप्पणी और न्यायिक नोटिस के लिए आया था। हमने जूरी से धारा 124 ए के स्पष्टीकरण के लिए आरोप को हटा दिया है। क्योंकि उस स्पष्टीकरण ने अब व्यक्त की गई न्यायिक राय को देखते हुए तीन अलग-अलग स्पष्टीकरणों को स्थान दिया है। जूरी ने छह से तीन के बहुमत से श्री बालगंगाधर तिलक को दोषी पाया। इसके बाद, उन्होंने, दोषसिद्धि पर, लेटर्स पेटेंट के खंड 41 के तहत आवेदन किया। 41 प्रिवी काउंसिल में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदित किया। आवेदन की

सुनवाई फारन, मुख्य न्यायाधीश, कैंडी एंड स्ट्रैची, न्यायाधीशगण की एक पूर्ण पीठ ने की। छुट्टी के स्तर पर उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था अन्य बातों के साथ कि सरकार द्वारा दी गई मंजूरी कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं थी क्योंकि उसने अपमानजनक अनुच्छेदों का विवरण निर्धारित नहीं किया था, और दूसरी बात यह कि न्यायाधीश ने जूरी को "असंतोष" शब्द के अर्थ के बारे में गलत निर्देश दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह "स्नेह की अनुपस्थिति" के बराबर हो सकता है। दूसरे बिंदु के संबंध में, जो हमारे सामने केवल प्रासंगिक बिंदु है; पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित प्रभाव को व्यक्त कियाः

> "दूसरा आधार जिस पर श्री रसेल ने यह प्रमाणित करने के लिए कहा है कि यह परिषद में महामहिम को भेजे जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है, वह यह है कि एक गलत दिशा निर्देश किया गया है, और उन्होंने अपना तर्क एक बड़े और दो छोटे आधारों पर आधारित किया है। प्रमुख आधार यह था कि इस धारा का उल्लंघन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि अव्यवस्था या विद्रोह को भड़काने के लिए कोई सीधा उकसावा न हो। हमें लगता है कि यह धारा के शब्दों से बहुत आगे जाते हुए, और हमें उस आधार पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मामूली बिंदुओं में से पहला यह है कि जस्टिस श्री स्ट्रैची ने जूरी के सामने मामले का सारांश देते हुए कहा कि असंतोष का मतलब स्नेह का अभाव है। लेकिन अगर वह वाक्यांश अकेला विद्यमान होता तो यह जूरी को गुमराह कर सकता था, फिर भी संदर्भ के संबंध में हमें लगता है कि यह असंभव है कि जूरी को इससे गुमराह किया जा सकता था। उस अभिव्यक्ति का उपयोग बंगोबाशी वाद में कलकत्ता में सर कॉमर पेथेरम के नेतृत्व में कानून के संबंध में किया गया था। वहाँ मुख्य न्यायाधीश ने "स्नेह की अनुपस्थिति" शब्दों का उपयोग करने के बजाय "स्नेह के विपरीत" शब्दों का उपयोग किया। यदि इस मामले में "स्नेह की अनुपस्थिति" के बजाय "स्नेह के विपरीत" शब्दों का उपयोग किया गया होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस विशेष में

सारांश पूरी तरह से सही होता। लेकिन संदर्भ के संबंध में यह स्पष्ट है कि "स्नेह की अनुपस्थिति" शब्दों से विद्वान न्यायाधीश का अर्थ स्नेह का निषेध नहीं था, बल्कि दूसरी ओर कुछ सक्रिय भावना थी। इसलिए उस बिंदु पर हम मानते हैं कि हम यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि यह अपील के लिए उपयुक्त मामला है।

इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि यह आरोप नहीं लगाया गया है कि न्याय की विफलता हुई है।"

उन टिप्पणियों को करने के बाद, पूर्ण पीठ ने छुट्टी के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद न्यायिक समिति में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन के माध्यम से मामले को परिषद में महामहिम के पास ले जाया गया। एस्क्विथ, क्यू. सी. काउंसिल के प्रभुत्व, जो मयने, डब्ल्यू. सी. बनर्जी एवं अन्य जैसे महान अनुभव एवं प्रतिष्ठित वकील द्वारा सहायता प्राप्त थे के समक्ष तर्क दिया कि दंड संहिता की धारा 124 ए के अर्थ के बारे में एक गलत दिशा थी जिसमें अपराध को प्रभाव को व्यापक करने के संदर्भ में परिभाषित किया गया था कि "असंतोष" का अर्थ केवल "स्नेह की अनुपस्थिति" है और यह सरकार के प्रति हर संभव रूप से बुरी भावना को समझता है। इस संबंध में क्वीन-इम्प्रेस बनाम जोगेंद्र बोस (1) में पेथेरम, सी. जे. की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की टिप्पणियाँ इंग्लैंड में एक सार्वजनिक पत्रकार के कार्यों के भीतर जो माना जाएगा, उससे अधिक नहीं था, और यह कि जिस गलत दिशा की शिकायत की गई थी, वह न केवल प्रभावित व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे भारतीय प्रेस और महामहिम के सभी व्यक्तियों के लिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी; और यह कि यह प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बैठकों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन विशेष अनुमति के लिए याचिकाकर्ता की ओर से की गई कड़ी अपील के बावजूद, लॉर्ड चांसलर ने न्यायिक समिति की राय देते हुए आवेदन को

खारिज करते हुए कहा कि पूरे सारांश को ध्यान में रखते हुए वे इससे असहमति का कोई कारण नहीं देखते हैं, और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो उनके प्रभुत्व ने आपराधिक मामलों में अपील करने की अनुमति देने के मामले में देखे थे, उन्हें नहीं लगता था कि मामला ऐसे सवाल उठाता है जो प्रिवी काउंसिल द्वारा आगे विचार के योग्य हैं। (गंगाधर तिलक बनाम रानी एम्प्रेस (1) के माध्यम से)

कानून में आगे के परिवर्तनों पर ध्यान देने से पहले, रानी महारानी एम्प्रेस बनाम अंबा प्रसाद (2) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख करना आवश्यक है। उस मामले में, एज, मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय दिया, ने उपरोक्त मामलों में कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के निर्णयों से प्रचुर उद्धरण दिए। साधारणतः उपरोक्त दो मामलों में निर्णयों के कारणों के बारे में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक व्यक्ति धारा 124 ए में परिभाषित अपराध जो 124 ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष की भावनाओं को भड़काने का प्रयास का दोषी हो सकता है, हालांकि किसी विशेष लेख या भाषण में वह सरकार का पालन करने और समर्थन करने की वांछनीयता या औचित्य पर जोर दे सकता है। उन्होंने सतारा (3) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया। उस मामले में एक पूर्ण पीठ, जिसमें फारन, मुख्य न्यायाधीश, और पार्सन्स और रानाडे, न्यायाधीशगण शामिल थे, यह निर्धारित किया गया था कि इस धारा में "असंतोष" शब्द का उपयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है जिसका अर्थ है राजनीतिक अपवर्तन या सरकार या मौजूदा प्राधिकरण के प्रति असंतोष या अविश्वास। उन्होंने यह भी माना कि धारा के मुख्य भाग में "असंतोष" शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण से भिन्न नहीं था। पार्सन्स, न्यायाधीश का मानना था कि "असंतोष" शब्द का अर्थ 'स्नेह या प्रेम की अनुपस्थिति या इसके विपरीत' के रूप में नहीं लिया जा सकता है। रानाडे न्यायाधीश ने "असंतोष" शब्द की व्याख्या केवल प्रेम या सद्भावना की अनुपस्थिति या निषेध के रूप में नहीं की, बल्कि घृणा की एक सकारात्मक भावना के रूप

में की, जो दुर्भावना से संबंधित है, अधिकार की एक निश्चित अवज्ञा या लोगों को अलग-थलग करने और निष्ठा के बंधन को कमजोर करने के समान है, एक ऐसी भावना जो सरकार को घृणा और असंतोष में लाती है, इसके लिए अधम और भ्रष्ट उद्देश्यों को आरोपित करती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि वे टिप्पणियां किसी भी अर्थ में स्ट्रेची, न्यायाधीश द्वारा धारा पर रखे गए निर्माण से अलग थीं, जिसे प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की बाद की टिप्पणियों को आधिकारिक नहीं माना जा सकता था। चूँकि इलाहाबाद मामले में अभियुक्तों ने दोष स्वीकार कर लिया था और अपील कमोबेश सजा के प्रश्न पर थी, इसलिए उनके प्रभुत्वों के लिए इस धारा के निहितार्थ की विस्तार से जांच करना आवश्यक नहीं था, हालाँकि उन्होंने ऊपर निर्दिष्ट पहले दो मामलों में कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण के साथ अपनी सामान्य सहमति व्यक्त की थी।

इस धारा को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम (1898 का चौथा) द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा के एकल स्पष्टीकरण को तीन अलग-अलग स्पष्टीकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो अब मौजूद हैं। यह धारा, जो अब अपने वर्तमान स्वरूप में है, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा और 1950 का भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 1937,1948 और 1950 के कई ए. ओ. एस. का परिणाम है। धारा 124 ए, जैसा कि यह उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से क्रमिक संशोधनों के बाद उभरा है, निम्नानुसार हैः

> "जो कोई भी शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा को अवमानना में लाता है या लाने का

प्रयास करता है, या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने या भड़काने के प्रयासों को आजीवन परिवहन या किसी भी छोटी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या कारावास जो तीन साल तक बढ़ सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1. "असंतोष" अभिव्यक्ति में बेवफाई और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2. घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्तेजित किए बिना या उकसाने का प्रयास किए बिना, वैध माध्यमों से उनके परिवर्तन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 3. घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्तेजित किए बिना या उकसाने का प्रयास किए बिना सरकार की अन्य कार्रवाई की प्रशासनिक अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं हैं।

यह अपराध, जिसे आम तौर पर राजद्रोह के अपराध के रूप में जाना जाता है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV में होता है, जिसका शीर्षक 'राज्य के खिलाफ अपराध' है। राज्य के खिलाफ अपराध की यह प्रजाति भारत में ब्रिटिश सरकार का आविष्कार नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में सदियों से जानी जाती रही है। प्रत्येक राज्य को, चाहे उसकी सरकार का कोई भी रूप हो, उन लोगों को दंडित करने की शक्ति से लैस होना चाहिए जो उनका आचरण, राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालता है, या बेवफाई की ऐसी भावनाओं का प्रसार करता है जो राज्य में व्यवधान या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण

बनती हैं। इंग्लैंड में, इस प्रकार अपराध का वर्णन स्टीफन ने इंग्लैंड के कानूनों पर अपनी टिप्पणियों, 21 वें संस्करण, खंड IV, पृष्ठ 141-142 में इन शब्दों में किया है।

"धारा IX राजद्रोह और असंतोष को भड़काना-अब हम ऐसे आचरण से चिंतित हैं जो एक ओर राजद्रोह से कम है, और दूसरी ओर बल या हिंसा का उपयोग शामिल नहीं है। कानून को यहां राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुरक्षित करने की आवश्यकता के साथ निजी आलोचना के अधिकार का मिलान करना है। राजद्रोह को ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका या तो उद्देश्य हो या इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में, सरकार या समाज की मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष का गैरकानूनी प्रदर्शन हो।

राजद्रोही आचरण शब्दों, कार्यों या लेखन द्वारा हो सकता है। अभियुक्त के उद्देश्य के अनुसार राजद्रोह के पाँच विशिष्ट प्रमुखों की गणना की जा सकती है। यह या तो

1. राजा, सरकार या संविधान के खिलाफ या संसद या न्याय प्रशासन के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए हो सकता है।

2. चर्च या राज्य में किसी भी परिवर्तन को गैरकानूनी तरीकों से बढ़ावा देना;

3. शांति भंग करने के लिए उकसाना;

4. राजा के प्रजा के बीच असंतोष बढ़ाने के लिए

5. वर्ग घृणा को भड़काना।

यह देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक मामलों पर आलोचना अपने आप में राजद्रोही नहीं है। परीक्षण वह तरीका है जिसमें इसे बनाया जाता है। स्पष्ट और

ईमानदार चर्चा की अनुमति है। कानून केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब चर्चा निष्पक्ष आलोचना की सीमा को पार कर जाती है। विशेष रूप से ऐसा तब होगा जब कैदी के आचरण का स्वाभाविक परिणाम सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

कानून का यह कथन मुख्य रूप से रेग बनाम अलेक्जेंडर मार्टिन सुलिवन (1) के मामले में फ़ित्जराल्ड, न्यायाधीश द्वारा जूरी को दिए गए सम्बोधन से लिया गया है। जूरी को अपने संबोधन के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"राजद्रोह समाज के खिलाफ एक अपराध है, जो लगभग राजद्रोह से संबद्ध है, और यह अक्सर थोड़े अंतराल में राजद्रोह से पहले होता है। राजद्रोह अपने आप में एक व्यापक शब्द है, और यह उन सभी प्रथाओं को शामिल करता है, चाहे वे शब्द, कार्य या लेखन द्वारा हों, जो राज्य की शांति को बिगाड़ने के लिए गणना की जाती हैं, और अज्ञानी व्यक्तियों को सरकार और साम्राज्य के कानूनों को नष्ट करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। राजद्रोह का उद्देश्य आम तौर पर असंतोष और विद्रोह को प्रेरित करना और सरकार के विरोध को भड़काना और न्याय प्रशासन को अवमानना में लाना है और राजद्रोह की प्रवृत्ति ही लोगों को विद्रोह और बगावत के लिए उकसाना है। राजद्रोह को कार्रवाई में बेवफाई के रूप में वर्णित किया गया है और कानून उन सभी प्रथाओं को राजद्रोह मानता है जिनका उद्देश्य असंतोष या असंतुष्टि को भड़काना, सार्वजनिक अशांति पैदा करना, या गृह युद्ध की ओर ले जाना है; प्रभुत्वक या सरकार, क्षेत्र के कानूनों या संविधान की घृणा या अवमानना करना, और आम तौर पर सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने के सभी प्रयास।

यह कि सदियों के दौरान कानून में कोई बदलाव नहीं आया है, कॉलरिज, न्यायाधीश द्वारा कानून के निम्नलिखित कथन से भी स्पष्ट है, जो रेक्स बनाम एल्ड्रेड (2) के मामले में जूरी के लिए अपने सारांश के दौरान था।

"इस शीर्ष पर कानून से अधिक स्पष्ट कुछ भी नहीं है-अर्थात्, जो कोई भी भाषा द्वारा या तो लिखित या मौखिक रूप से राज्य से जुड़े किसी सार्वजनिक मामले में दूसरो को शारीरिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए उकसाता है या प्रोत्साहित करता है, वह राजद्रोही मानहानि प्रकाशित करने का दोषी है। "राजद्रोह" शब्द अपने सामान्य प्राकृतिक अर्थ में एक उथल-पुथल, एक विद्रोह, एक लोकप्रिय हंगामा या एक कोलाहल को दर्शाता है; यह किसी न किसी रूप में हिंसा या अराजकता को दर्शाता है।...."

उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश अभ्यारोपण के संबंध में जूरी पर आरोप लगा रहे थे जिसमें प्रतिवादी द्वारा एक प्रकाशन द्वारा राजद्रोही मानहानि का आरोप था।

नियम 34(6) (ई), भारत रक्षा अधिनियम (1939 का XXXV) से उदभूत वाद पर विचारण के तहत भारत रक्षा नियमों के) सर मौरिस ग्वायर, मुख्य न्यायाधीश ने संघीय न्यायालय की ओर से बोलते हुए, निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम राजा सम्राट (1) के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं; और इंगित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की भाषा, जो प्रश्नगत नियम के समान था, अंग्रेजी कानून से अपनाया गया था, और ऊपर उद्धृत मामले में फ़ित्जराल्ड, न्यायाधीश की टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था; और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं जो काफी उपयुक्त हैंः

".....आम तौर पर बोलते हुए, हम सोचते हैं कि परिच्छेद कानून को सटीक रूप से बताता है क्योंकि इसे बड़ी संख्या में न्यायिक घोषणाओं की जांच से एकत्र किया जाना है।

प्रत्येक सरकार का पहला और सबसे मौलिक कर्तव्य व्यवस्था का संरक्षण है, क्योंकि व्यवस्था सभी सभ्यताओं और मानव सुख की प्रगति के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कर्तव्य कभी-कभी इस तरह से किया गया है कि

> उपचार को रोग से भी बदतर बनाने का एक तरीका हो; लेकिन यह दायित्व का विषय होने से रुकता नहीं है क्योंकि कुछ लोगों जिन पर कर्तव्य है, उन्होंने इसे खराब तरीके से किया है। यह सरकारी कार्यों के इस पहलू के लिए है कि हमारी राय में राजद्रोह का अपराध संबंधित है। यह उन लोगों के लिए राज्य का जवाब है, जो उस पर हमला करने या उसे नष्ट करने के उद्देश्य से, उसकी शांति भंग करने, सार्वजनिक अशांति पैदा करने और अव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए (ऊपर उद्धृत परिच्छेद से उधार लेने के लिए) की माँग करते हैं या जो दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। शब्द, कर्म या लेखन राजद्रोह का गठन करते हैं, यदि उनका यह इरादा या प्रवृत्ति है और यह समझना आसान है कि वे राजद्रोह का भी गठन क्यों कर सकते हैं, यदि वे, जैसा कि वाक्यांश है, सरकार को अवमानना में लाने की तलाश चाहते हैं। इसे सरकार के घायल अहंकार की सेवा करने के लिए अपराध नहीं बनाया गया है, लेकिन क्योंकि जहां सरकार और कानून का पालन करना बंद हो जाता है क्योंकि उनके लिए अब कोई भी सम्मान महसूस नहीं किया जाता है, केवल अराजकता ही हो सकती है। सार्वजनिक अव्यवस्था, या सार्वजनिक अव्यवस्था की उचित प्रत्याशा या संभावना, इस प्रकार अपराध का सार है। जिन कार्यों या शब्दों की शिकायत की गई है, उन्हें या तो अव्यवस्था के लिए उकसाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो उचित लोगों को संतुष्ट करे जो उनकी मंशा या प्रवृत्ति है।

राजा-सम्राट बनाम सदाशिव नारायण भालेराव (1) के मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के प्रभुत्व द्वारा कानून के इस कथन को मंजूरी नहीं दी गई थी। प्रिवी काउंसिल ने निहारेन्दु के मामले (2) में विद्वान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को उद्धृत करने के बाद, संघीय न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा कि इंग्लैंड में "राजद्रोह" की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, और अपराध का अर्थ और सामग्री किसी भी निर्णय से एकत्र की जानी चाहिए। लेकिन वे प्रासंगिक विचार नहीं थे जब संहिता में 'राजद्रोह' की वैधानिक

परिभाषा का अर्थ लगाना पड़ता था। प्रिवी काउंसिल ने माना कि धारा 124 ए की भाषा या भारत सरकार अधिनियम के तहत उपरोक्त नियम, निहारेन्दु के मामले में विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए कानून के बयान को उचित नहीं ठहराता है। उन्होंने यह भी माना कि " असंतोष को उत्तेजित करना" अभिव्यक्ति में "अव्यवस्था को उत्तेजित करना" शामिल नहीं है, और इसलिए, निहारेन्दु के मामले में (1) संघीय न्यायालय का निर्णय दंड संहिता के धारा 124 ए और भारत रक्षा नियमों के नियम 34 का उप-पैरा (ई), उप-नियम (6); के गलत निर्माण पर आगे बढा, बाल गंगाधर तिलक (2) के मामले में उनके प्रभुत्व ने कथन को मंजूरी दी, और एनी बसंत बनाम मद्रास के महाधिवक्ता (3) के मामले में, जो भारतीय प्रेस अधिनियम। (1910 का I), के धारा 4 के तहत एक मामला था, जो भाषा में दंड संहिता की धारा 124 ए के समक्ष था। 124 दंड संहिता का ए।

प्रिवी काउंसिल ने वालेस जॉनसन बनाम द किंग (4) में अपने पिछले निर्णय का भी उल्लेख किया जो गोल्ड कोस्ट की आपराधिक संहिता की धारा 326 की उप धारा 8 के तहत एक मामला था, जो दंड संहिता की धारा 124 ए .जो दंड संहिता की धारा 124 ए के शब्दों के समान शब्दों में "राजद्रोही इरादे" को परिभाषित करती है। .उस मामले में, उनके अधिपतियों ने निर्धारित किया था कि हिंसा के लिए उकसाना राजद्रोह के अपराध का आवश्यक घटक नहीं था जैसा कि उस कानून में परिभाषित किया गया था।

इस प्रकार, निहारेन्दु के मामले (1) में संघीय न्यायालय के निर्णय और ऊपर उल्लिखित भारतीय और गोल्ड कोस्ट के कई मामलों में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बीच सीधा टकराव है। यह भी स्पष्ट है कि किसी भी दृष्टिकोण को लिया जा सकता है और अच्छे कारणों से इसका समर्थन किया जा सकता है। संघीय न्यायालय का निर्णय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजद्रोह के संबंध में इंग्लैंड के पूर्व-निकास सामान्य कानून को ध्यान में रखता है। संघीय न्यायालय का निर्णय के प्रतिवेदन से यह प्रतीत नही होता है कि प्रिवी

काउंसिल के उपरोक्त फैसलों को संघीय न्यायालय के उनके प्रभुत्व के ध्यान में लाया गया था।

जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, मामलों के इस समूह में निर्धारण के लिए सीधे उत्पन्न होने वाला प्रश्न पहले निर्णय का विषय नहीं बना है। लेकिन कुछ मामलों में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां, जिन पर वर्तमान में ध्यान दिया जाना चाहिए, भाषण की स्वतंत्रता और राजद्रोही लेखन या बोलने के बीच अंतर्संबंध के संदर्भ में संविधान के लागू होने के पहले वर्ष में की गई हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर विचार करने वाले दो मामले और उस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले कुछ राज्यों द्वारा अधिनियमित कुछ कानून इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1) और बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (2) में दर्ज उन मामलों की सुनवाई कनिया मुख्य न्यायाधीश, पज़ल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और दास, न्यायाधीशगण ने की थी और निर्णय उसी दिन (26 मई, 1950) दिए गए थे। रोमेश थापर के मामले (1) में, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट (मैड 1949 का XXIII) में न्यायालय के बहुमत से घोषित धारा (1ए), जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत किया था, ऐसे प्रतिबंधों को प्राधिकृत करने वाले संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) से अधिक होना चाहिएऔर इसलिए, अमान्य और असंवैधानिक है। बृज भूषण के मामले (2) में, समान बहुमत ने पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1949 की धारा 7(1)(सी) को खारिज कर दिया, जैसा कि दिल्ली प्रांत तक विस्तारित किया गया है, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी गतिविधि को रोकने या उसका मुकाबला करने के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करता है या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने को। न्यायालय ने उन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) द्वारा विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों से अधिक माना है। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने रोमेश थापर के मामले (1) में न्यायालय के बहुमत

की ओर से बोलते हुए संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के फैसलों के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं कि भारत में राजद्रोह का कानून क्या थाः

"यह भी ध्यान देने योग्य है कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 13 (2) में आया "राजद्रोह" शब्द को अनुच्छेद 19 (2) के रूप में अंतिम रुप में पारित करने से पहले हटा दिया गया था। इस संबंध में यह याद किया जा सकता है कि संघीय न्यायालय ने निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम राजा सम्राट (2) में राजद्रोह को परिभाषित करते हुए कहा था कि "शिकायत किए गए कार्यों या शब्दों को या तो अव्यवस्था के लिए उकसाना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जिससे उचित लोगों को संतुष्ट किया जा सके कि यह उनका इरादा या प्रवृत्ति है", लेकिन प्रिवी काउंसिल ने उस निर्णय को खारिज कर दिया और तिलक के मामले में व्यक्त किए गए विचार की इस प्रभाव से पुष्टि की कि "अपराध सरकार के प्रति कुछ बुरी भावनाओं को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास करने में शामिल था, न कि उत्तेजना में या विद्रोह या बगावत को उत्तेजित करने के प्रयास में, या किसी भी प्रकार की वास्तविक अशांति, बड़ी या छोटी"-राजा सम्राट बनाम सदाशिव नारायण भालेराव। इसलिए, अनुच्छेद 13 (2) के मसौदे से "राजद्रोह" शब्द को हटाना दर्शाता है कि सरकार की आलोचना को उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को भड़काने के लिए अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक उचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि यह राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने या राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति वाला न हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित "सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य के अधिकार को कम करने" के आयरिश सूत्र (अग्नि संविधान, 1937 का अनुच्छेद 40 (6) (i)) को स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के निर्माताओं का समर्थन नहीं मिला। इस प्रकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुमेय विधायी संक्षिप्तकरण के लिए बहुत संकीर्ण और

> सख्त सीमाएं निर्धारित की गई हैं, और यह निस्संदेह कि बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर है, क्योंकि मुफ्त राजनीतिक चर्चा के बिना कोई भी सार्वजनिक शिक्षा, जो लोकप्रिय सरकार की प्रक्रियाओं के उचित संचालन के लिए इतनी आवश्यक है, संभव नहीं है, इस तरह की स्वतंत्रता में दुरुपयोग के जोखिम शामिल हो सकते हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने मैडिसन के साथ अच्छी तरह से प्रतिबिंबित किया होगा, जो "संघीय संविधान के पहले संशोधन की तैयारी में अग्रणी भावना थी" कि "इसकी कुछ खराब शाखाओं को उनके शानदार विकास पर छोड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उन्हें उचित फल देने वालों की शक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए काट दिया जाए":(नियर बनाम मिनेसोटा में उद्धृत)।

ये टिप्पणियां "राज्य की सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के बीच के अंतर को सामने लाने के लिए की गई थीं। चूंकि बाद की अभिव्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में जगह नहीं मिली, जैसा कि यह मूल रूप से था, इस धारा को असंवैधानिक के रूप में निरस्त कर दिया गया था। फज़ल अली, न्यायाधीश ने बहुमत द्वारा इस प्रकार व्यक्त किए गए विचारों से असहमति जताई और बृज भूषण के मामले में अपनी टिप्पणियों को दोहराया (1) अपने असहमत निर्णय के दौरान, उन्होंने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> "मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम विश्लेषण में इस मामले में तय किया जाने वाला वास्तविक सवाल यह है कि क्या "प्रांत की शांति एवं अमन के लिए अव्यवस्था से जुड़े खतरे हैं।" और "सार्वजनिक सुरक्षा" को प्रभावित करना एक ऐसा मामला होगा जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है या नहीं। मैंने अधिनियम की प्रस्तावना से उद्धरण चिन्ह के भीतर उद्धृत शब्दों को उधार लिया है जो इसके दायरे और आवश्यकता को दर्शाता है और अधिनियम की वैधता पर हमला करने के

लिए हमारे सामने उठाए गए प्रश्न को मेरे सुझाव के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, जैसा कि मुझे लगता है कि यह होना चाहिए, तो विवादित कानून जो सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए "किसी भी दस्तावेज या दस्तावेजों के वर्ग" के मद्रास राज्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, उसे संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हमें संबोधित तर्कों की प्रवृत्ति से, यह प्रतीत होता है कि यदि कोई दस्तावेज़ राजद्रोही है, तो उसके प्रवेश को वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि राजद्रोह एक ऐसा मामला है जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है; लेकिन अगर दूसरी ओर, दस्तावेज़ को सार्वजनिक शांति को बाधित करने और सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए माना जाता है, तो इसके प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक अव्यवस्था और सार्वजनिक शांति को बाधित करना ऐसे मामले नहीं हैं जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करते हैं। अपने लिए बोलते हुए, मैं इस तर्क को नहीं समझ सकता। बृज भूषण बनाम राज्य में। मैंने यह दिखाने के लिए अच्छे अधिकार का हवाला दिया है कि राजद्रोह की गंभीरता आपराधिक कानून पर विकार और अधिकार पैदा करने की इसकी प्रवृत्ति के कारण है जैसे सर जेम्स स्टीफन ने राजद्रोह को सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध के रुप में वर्गीकृत किया है।”

बृजभूषण मामले (1) में, फजल अली, न्यायाधीश जो फिर से असहमत न्यायाधीश थे, ने अपने कारणों को अधिक विस्तार से बताया। उन्होंने निहारेन्दु दत्त मजूमदार के मामले में (2) संघीय अदालत के फैसले का उल्लेख किया और राजा सम्राट बनाम सदा शिव नारायण (1) में इसके विपरीत प्रिवी काउंसिल के निर्णय के लिए। भारतीय संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के बीच मतभेद को इंगित करने के बाद, विद्वान

न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में "राजद्रोह" शब्द का विशेष रूप से उल्लेख क्यों नहीं किया गया थाः

> "इसलिए संविधान निर्माताओं को इस दुविधा का सामना करना पड़ा होगा कि क्या "राजद्रोह" शब्द का उपयोग अनुच्छेद 19 (2) में किया जाना चाहिए और अगर इसका उपयोग किया जाता था तो किस अर्थ में किया जाना चाहिए। एक ओर, उनके दिमाग के सामने कई अधिकारियों द्वारा समर्थित बहुत व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए कि राजद्रोह अनिवार्य रूप से सार्वजनिक शांति के खिलाफ एक अपराध था और किसी न किसी तरह से सार्वजनिक अव्यवस्था से जुड़ा था; और दूसरी ओर, न्यायिक समिति की घोषणा थी कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित राजद्रोह आवश्यक रूप से अव्यवस्था भड़काने के किसी भी इरादे या प्रवृत्ति का संकेत नहीं देता था। इन परिस्थितियों में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने खंड (2) में "राजद्रोह" शब्द का उपयोग नहीं करने का फैसला किया, लेकिन अधिक सामान्य शब्दों का उपयोग किया जो राजद्रोह और अन्य सभी चीजों को शामिल करते हैं जो राजद्रोह को इतना गंभीर अपराध बनाते हैं। कि राजद्रोह राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई संदेह नहीं है। यह भी कि यह आम तौर पर सार्वजनिक अव्यवस्था के माध्यम से राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, एक ऐसा मामला है जिस पर प्रतिष्ठित न्यायाधीशों और न्यायविदों में सहमति है। इसलिए, यह मानना मुश्किल है कि सार्वजनिक अव्यवस्था या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी ऐसे मामले नहीं हैं जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करते हैं।"

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) की व्याख्या में उनके मतभेदों के परिणामस्वरूप, संसद ने अनुच्छेद 19 के खंड (2) में इस प्रकार संशोधन किया जिसमे यह वर्तमान में है, अधिनियम की धारा 3 द्वारा जिसने मूल खंड (2) को नए खंड (2) द्वारा प्रतिस्थापित

किया। यह संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ किया गया था, इस प्रकार यह संकेत देता है कि यह फजल अली, न्यायाधीश के असहमत निर्णय में निहित कानून के बयान को स्वीकार करता है, जहाँ तक कि उन्होंने बताया था कि "राज्य की सुरक्षा" की अवधारणा "सार्वजनिक व्यवस्था" की अवधारणा से बहुत अधिक संबद्ध थी और यह कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वैध रूप से लगाए जा सकते हैं।

पुनः रामजी लाल मोदी बनाम यू.पी. राज्य के मामले में इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) एवं 19(2) के प्रावधानों के संदर्भ के साथ विधायी शक्तियो की सीमाओं का प्रश्न आया। उस मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए की वैधता इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। .इस संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "हमारे विचार के लिए सवाल यह है कि क्या विवादित धारा को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून उचित रूप से कहा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि संशोधित खंड में प्रयुक्त भाषा "के हित में" है न कि "के रखरखाव के लिए"। जैसा कि हममें से एक ने देवी सरों बनाम बिहार राज्य के मामले में बताया है, "के हितों में" अभिव्यक्ति सुरक्षा के दायरे को बहुत व्यापक बनाती है। सार्वजनिक व्यवस्था को सीधे बनाए रखने के लिए एक कानून डिजाईन नही किया गया होगा और फिर भी इसे सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित किया गया होगा।"

यद्यपि ऊपर उद्धृत टिप्पणियाँ वर्तमान विवाद पर प्रत्यक्ष रूप से असर नहीं डालती हैं, वे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए विधायिका की शक्ति के दायरे पर काफी प्रकाश डालती हैं।

इस मामले में, हम सीधे इस सवाल से चिंतित हैं कि अपराध के लिए कैसे, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 129ए को परिभाषित संविधान के अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के अनुरूप है, जो इन शर्तों में हैः

"19. (1) सभी नागरिकों को इसका अधिकार है।

(ए) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए।

यह गारंटीकृत अधिकार उचित प्रतिबंध लगाने के विधानमंडल के अधिकार के अधीन है, जिसका दायरा खंड (2) द्वारा इंगित किया गया है। जो अपने संशोधित रूप में इस प्रकार हैः

"(2) खंड (1) के उपखंड (ए) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है।

हमारे सामने इस बात पर सवाल नहीं उठाया गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यह सामान्य आधार है कि अधिकार ऐसे उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो खंड (2) के दायरे में आते हैं। जिसमें (ए) राज्य की सुरक्षा, (बी) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रपूर्ण संबंध, (सी) सार्वजनिक व्यवस्था, (डी) शालीनता या नैतिकता, आदि। भारतीय दंड संहिता की धारा

124 ए या धारा 505 के संवैधानिकता के संदर्भ में, जहाँ तक वे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में, अनुच्छेद 19 के खंड (2) की आवश्यकताओं के अनुरुप है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी बोले गए या लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्य अभ्यावेदन, आदि को धारा दंडित करती है, या जो कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजना या असंतोष को भड़काते है या भड़काने का प्रयास करते है एवं प्रभावित करते है को वर्तमान समय के लिए उन व्यक्तियों को अलग किया जाता है जो प्रशासन करने में व्यस्त है। "कानून द्वारा स्थापित सरकार "राज्य का दृश्य प्रतीक है। यदि कानून द्वारा स्थापित सरकार को नष्ट कर दिया जाता है तो राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है। यही कारण है कि 'राजद्रोह', धारा 124 ए में अपराध के रुप में विशेषकर है जो राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्याय VI के तहत आता है। अतः धारा 124 ए के अर्थ के भीतर कोई भी कार्यजो उस सरकार को अवमानना या घृणा में लाकर या उसके खिलाफ असंतोष पैदा करके सरकार को नष्ट करने का प्रभाव डालता है, वह दंडात्मक कानून के भीतर होगा क्योंकि कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अविश्वास या उसके प्रति शत्रुता की भावना वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए उकसावे के उपयोग से सार्वजनिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति के विचार को आयात करती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी लिखित या बोले गए शब्द, आदि, जिनमे हिंसक माध्यमों से सरकार को नष्ट करने का विचार निहित करते हैं, जिन्हें 'क्रांति' शब्द में समग्र रूप से शामिल किया गया है, को प्रश्नगत धारा द्वारा दंडित किया गया है। लेकिन इस धारा ने यह स्पष्ट रूप से इंगित करने का ध्यान रखा है कि सरकार के उपायों के सुधार या विधिसम्मत माध्यमों से परिवर्तन की दृष्टि से उनकी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कठोर शब्द इस धारा के भीतर नहीं आएंगे। इसी तरह, टिप्पणियाँ, चाहे जोरदार शब्दों में हो, हिंसा के कृत्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करने वाली भावनाओं को उत्तेजित किए

बिना, सरकार के कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करना दंडनीय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति बेवफाई सरकार या उसकी एजेंसियों के उपायों या कार्यों पर कठोर शब्दों में टिप्पणी करने के समान नहीं है, ताकि लोगों की स्थिति में उन्नति हो सके या उन कार्यों या उपायों को वैध तरीकों से रद्द या परिवर्तन किया जा सके, यानी उन शत्रुता और बेवफाई की भावनाओं को उत्तेजित किए बिना जो सार्वजनिक अव्यवस्था या हिंसा के उपयोग के लिए उत्तेजना का संकेत देते हैं।

हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि यदि कोई भाषण या लेखन लोगों को हिंसा के लिए उत्तेजित करता है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है, तो यह 'राजद्रोह' की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा। जो तर्क दिया गया है वह यह है कि जो व्यक्ति बहुत कठोर भाषण देता है या सरकार के उपायों या लोक अधिकारियों के कार्यों की बहुत कठोर आलोचना करने के लिए लिखित में बहुत जोरदार शब्दों का उपयोग करता है, वह भी दंडात्मक धारा के दायरे में आ सकता है। लेकिन, हमारी राय में, ऐसे लिखित या बोले गए शब्द धारा के दायरे से बाहर होंगे। इस संबंध में, यह देखना उचित है कि राज्य की सुरक्षा, जो कानून और व्यवस्था के रखरखाव पर निर्भर करती है, बहुत ही बुनियादी विचार है जिस पर राज्य के खिलाफ अपराधों को दंडित करने के लिए कानून बनाया जाता है। इस तरह का कानून, एक ओर, पूरी तरह से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और गारंटी के लिए है, जो कि हमारे संविधान द्वारा स्थापित सरकार के लोकतांत्रिक रूप की अनिवार्यता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक और गारंटर के रूप में इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी भी ऐसे कानून जो इस वाद से संबंधित है एवं जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है, को रद्द करें। लेकिन स्वतंत्रता की फिर से रक्षा करनी होगी जो कानून द्वारा स्थापित सरकार की तिरस्कार और निंदा के लिए एक लाइसेंस बनना है एवं, शब्दों में जो हिंसा को उकसाता है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति रखता है। एक नागरिक को आलोचना या

टिप्पणी के माध्यम से सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी वह चाहे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से हिंसा के लिए नहीं उकसाता है। इसलिए, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत नागरिक के मौलिक अधिकार के दायरे और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित के साथ उस गारंटीकृत अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की विधायिका की शक्ति के बीच सीमांकन की एक स्पष्ट रेखा तैयार करे। इसलिए, हमें यह निर्धारित करना है कि भारतीय दंड संहिता के धारा 124 ए और 505 को कहाँ तक विधान की न्यायोचित सीमाओं के भीतर कहा जा सकता है। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है, तो निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम राजा सम्राट (1) के मामले में संघीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप कि 'राजद्रोह' के अपराध का सार हिंसा के लिए उकसाना या बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा है, जिसमें कानून द्वारा स्थापित सरकार को घृणा या अवमानना में लाने या राज्य के प्रति अविश्वास के अर्थ में असंतोष पैदा करने की प्रवृत्ति या प्रभाव है, दूसरे शब्दों में कानून को इंग्लैंड में राजद्रोह के कानून के अनुरूप लाना, जैसा कि विधायकों का इरादा था जब उन्होंने 1870 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में लाया होगा, संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर होगा, यदि .दूसरी ओर हम उस धारा के शब्दों को शाब्दिक अर्थ देते हैं, जो उन सभी पूर्व पृष्ठभूमि से अलग है जिसमें राजद्रोह का कानून विकसित हुआ है, जैसा कि प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह कहना सही होगा की धारा खंड (2) में निर्धारित सीमा के केवल भीतर है, बल्कि निर्धारित सीमाओं से बहुत परे है।

ऊपर निर्दिष्ट संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल के परस्पर विरोधी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा

124 ए एवं 505 के प्रावधान को कितने हद तक असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया जाना चाहिए। .यदि हम राजद्रोह के कथित अपराध में आपराधिकता के सार के रूप में संघीय न्यायालय की व्याख्या को स्वीकार करते हैं, अर्थात्, अव्यवस्था के लिए उकसाना या प्रवृत्ति या सार्वजनिक अव्यवस्था की संभावना या उचित आशंका, तो यह धारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुमेय विधायी प्रतिबंधों के दायरे में हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 19 के (2) के प्रावधानों के अलावा, धाराएँ124 ए और 505 स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन करते हैं। लेकिन फिर हमें यह देखना होगा कि बचत खंड, अर्थात्, अनुच्छेद 19 का खंड (2) कितनी दूर तक उपरोक्त धाराओं की रक्षा करती हैं। अब, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऊपर उद्धृत, संशोधित खंड (2) के संदर्भ में अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" बहुत विस्तार के शब्द हैं और "के रखरखाव के लिए" अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक व्यापक हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विरेंद्र बनाम पंजाब राज्य (1) के मामले में देखा गया है। सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित किसी भी कानून को संवैधानिक अयोग्यता के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि हम यह मानते हैं कि कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की किसी भी प्रवृत्ति या इरादे के बिना, लिखित या बोले गए शब्दों के उपयोग से जो केवल सरकार के खिलाफ असंतोष या शत्रुता की भावना पैदा करते हैं, तो राजद्रोह का अपराध पूर्ण है, तो धाराओं की ऐसी व्याख्या उन्हें अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ पठित खंड (2) के दृष्टिकोण से असंवैधानिक बना देगा। यह अच्छी तरह से.तय किया गया है कि यदि कानून के कुछ प्रावधानों का एक तरह से अर्थ लगाया जाए तो वे संविधान के अनुरूप हैं, और एक अन्य व्याख्या उन्हें असंवैधानिक बना देगी, न्यायालय पूर्व निर्माण के पक्ष में झुक जाएगा। व्याख्याओं के साथ-साथ समग्र रूप से पठित धाराओं के प्रावधान यह यथोचित रूप से स्पष्ट करते हैं कि धाराओं का उद्देश्य केवल ऐसी गतिविधियों को दंडित करना है जिनका उद्देश्य या एक प्रवृत्ति का होना कि हिंसा का सहारा लेकर

सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या गड़बड़ी पैदा करना है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, धारा के मुख्य भाग से जुड़े स्पष्टीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक उपायों की आलोचना या सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी, चाहे कितनी भी जोरदार हो, उचित सीमाओं के भीतर होगी और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुरूप होगी। यह केवल तभी होता है जब लिखित या बोले गए शब्द, जिनमें सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता है, कि कानून सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाता है। इस तरह से समझा गया, हमारी राय में, यह धारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के हित के बीच सही संतुलन बनाती है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय न्यायालय को न केवल उपयोग किए गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि कानून के पूर्व इतिहास, इसके उद्देश्य और उस शरारत को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसे वह दबाना चाहता है (दृश्य (1))। बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1) और (2) आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम भारत संघ (2) के माध्यम से। इस दृष्टि से देखने पर, हमें इन मामलों में आक्षेपित धाराओं के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाने में कोई संकोच नहीं है कि उनके अनुप्रयोग को अव्यवस्था पैदा करने के इरादे या प्रवृत्ति, या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, या हिंसा के लिए उकसाने वाले कार्यों तक सीमित कर दिया जाए।

हम कानूनी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं, जैसा कि यह उभरना चाहिए, यह मानते हुए कि मुख्य एस। धारा 124 ए का शाब्दिक अर्थ में अर्थ लगाया जा सकता है जिसमें प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने ऊपर निर्दिष्ट मामलों में इसका अर्थ लगाया है। उस धारणा पर, इस न्यायालय के लिए यह समझाना खुला नहीं है कि धारा एक ऐसा तरीका है जिससे धारा के आवेदन को उस तरह से सीमित करके कथित असंवैधानिकता से बचा जा सके जिस तरह से संघीय न्यायालय ने इसे लागू करने का इरादा किया था?हमारी

राय में, इस न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं जो कानूनी स्थिति के बारे में हमारे उस दृष्टिकोण को उचित ठहराते हैं। आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम भारत संघ (1) के मामले में इस न्यायालय ने इस न्यायालय के साथ-साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के न्यायालयों के कई निर्णयों की विस्तार से जांच की है। उन निर्णयों की जांच करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि किसी कानून के विवादित प्रावधान विवादित धारा या अधिनियम के शब्दों में से एक दृष्टिकोण को अपनाकर विधायिका की संवैधानिक शक्तियों के भीतर आते हैं, तो न्यायालय मामले के उस दृष्टिकोण को लेगा और तदनुसार अपने आवेदन को सीमित करेगा, उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए जो प्रश्नगत शब्दों की व्याख्या के दूसरे दृष्टिकोण पर इसे असंवैधानिक बना देगा। उस मामले में, न्यायालय को 'पुरस्कार प्रतियोगिताओं' अभिव्यक्ति की परिभाषा के बीच चयन करना था जो उन प्रतियोगिताओं तक सीमित थी जो जुआ खेलने की प्रकृति की थीं और जो नहीं थीं। न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को चुना जिसने अधिनियम, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (1955 का XLII) के शेष प्रावधानों को अधिनियम के धाराएँ 4 एवं 5 के विशेष संदर्भ के साथ और उसके तहत बनाए गए नियम 11 और 12 वैध हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जुर्माना केवल उन प्रतियोगिताओं के लिए लगाया जाता है जिनमें जुआ का तत्व शामिल होता है और उन प्रतियोगिताओं के लिए जिसमें सफलता कौशल पर काफी हद तक निर्भर करती है, अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाता है। उस मामले में निर्णय लेने का अनुपात, हमारी राय में, वर्तमान मामले पर लागू होता है जहाँ तक कि हम इसके संचालन को केवल ऐसी गतिविधियों तक सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं जो इसके दायरे में आती हैं। संघीय न्यायालय की टिप्पणियाँ, अर्थात, हिंसा को उकसाने वाली गतिविधियाँ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में बाधा डालने का इादा या प्रवृत्ति को शामिल करता है। हम पृष्ठ 940 से 952 पर आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम भारत संघ (1) के मामले में उद्धृत और चर्चा किए गए अधिकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने या

संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि विवादित धाराओं के प्रावधान, बोलने और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में और उस मौलिक अधिकार के साथ अनुमेय विधायी हस्तक्षेप के दायरे में नहीं कहा जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 505 की संवैधानिकता के संबंध में कुछ टिप्पणियों को जोड़ना आवश्यक है। .धारा के तीन खंडों में से प्रत्येक के संदर्भ में, यह पाया जाएगा कि अपराध की गंभीरता किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को बनाना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना है (ए) सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी सदस्य को विद्रोह करने या अन्यथा अपने कर्तव्य में उपेक्षा या विफल होने का कारण बनने की संभावना है; या (बी) जनता या जनता के एक वर्ग के लिए भय या चेतावनी पैदा करना जो राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है; या (सी) किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए एक वर्ग या व्यक्तियों के समुदाय को उकसाना या उकसाने की संभावना यह स्पष्ट है कि धारा 505 के तहत अपराध के घटक तत्वों में से प्रत्येक। राज्य या सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा का संदर्भ और उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, ये प्रावधान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंधों की सीमा से अधिक नहीं होंगे। यह स्पष्ट है, इसलिए, वह अनुच्छेद 19 का खंड (2) स्पष्ट रूप से इस धारा को असंवैधानिकता के दुष्प्रभाव से बचाता है।

1957 की सी.ए. 169 में अपीलार्थी की ओर से या अन्य अपीलों (1958 की सं. 124-126) में प्रत्यर्थियों की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्द राजद्रोह की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं जैसा कि हमारे द्वारा व्याख्या की गई है। हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया था कि हमारे द्वारा दी गई व्याख्या पर भी उनके मामले एक या दूसरी धारा की शरारत के दायरे में नहीं

आए, जैसा भी मामला हो। अतः 1957 की आपराधिक अपील 169 को खारिज करना पड़ता है। 1958 की आपराधिक अपील संख्या- 124-126 को उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने के लिए भेजा जाएगा जो वह हमारे द्वारा दी गई व्याख्या के आलोक में उचित और मुनासिब समझे।

1957 की अपील सं. 169 खारिज कर दी गई। 1958 की 124 से 126 तक की अपीलों की अनुमति दी गई।